नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. UPHIN/25/A1698

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 034
दि. 03.06.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

यूपी का 'फाजिलनगर' अब 'पावागढ़' होगा, सीएम योगी ने कुशीनगर में किया ऐलान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में आयोजित एक जनसभा के दौरान बड़ा ऐलान किया। उन्होंने भगवान महावीर से जुड़े ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले 'फाजिलनगर' का नाम बदलकर 'पावागढ़' करने की घोषणा की।

(जीएनएस)।

कुशीनगर, उत्तर प्रदेशः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में आयोजित जनसभा के दौरान 424 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देते हुए विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भगवान महावीर से जुड़े ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले फाजिलनगर का नाम बदलकर 'पावागढ़' करने का ऐलान भी किया।

कुशीनगर को कई चुनौतियों से पड़ता था जूझना

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 9-10 साल पहले कुशीनगर कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा था। उन्होंने कहा कि उस समय जिले को पहचान के संकट, बीमारियों, खनन और बालू माफियाओं के प्रभाव तथा 'जंगल पार्टी' के आतंक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था।

आतंक से सबसे अधिक प्रभावित था ये जिला

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 25 वर्ष से कम उम्र की पीढ़ी शायद उस दौर को न जानती हो, लेकिन

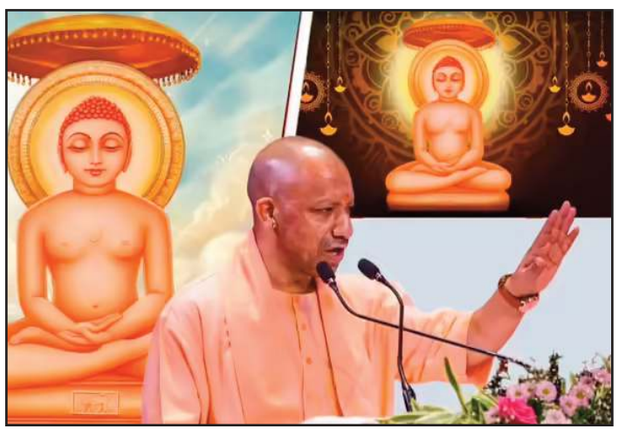

कुशीनगर उन जिलों में शामिल था जो इस आतंक से सबसे अधिक प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि इंसेफ्लाइटिस जैसी गंभीर बीमारी मासूम बच्चों की जान ले रही थी, जबकि किसान भी विभिन्न समस्याओं से परेशान थे। गन्ना किसानों को समय पर पर्ची नहीं मिलती थी और मिल जाने पर भी घटतौली की शिकायतें आम थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में सरकार ने इन चुनौतियों पर प्रभावी ढंग से काम किया है।

सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना

पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि एक समय ऐसा था जब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि गरीबों को फ्री राशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियों के कारण गरीब भूख और अभाव से जूझने को मजबूर थे, नौजवान बेरोजगारी की समस्या से परेशान थे और किसान कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। साथ ही आम जनता माफिया और अपराधियों के भय में जीवन बिताने को मजबूर थी।

यूपी के अंदर कोई सुविधा नहीं थी

मुख्यमंत्री ने कहा कि उस दौर में यूपी के अंदर कोई सुविधा नहीं थी। राज्य की पहचान भी संकट में थी। उन्होंने आरोप लगाया कि त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान अक्सर तनाव और दंगों की घटनाएं सामने आती थीं। पडरौना के डोल मेले का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय हुई हिंसा के बाद न्याय की मांग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।

दक्षिण अफ्रीका के उप राष्ट्रपति श्री शिपोकोसा पॉलस माशातिले ने उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की

भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए दक्षिण अफ्रीका के उप राष्ट्रपति श्री शिपोकोसा पॉलस माशातिले ने आज उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। उप राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात में उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तथा दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध प्रगाढ़ बनाने पर सार्थक चर्चा की।

उन्होंने विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और ब्रिक्स, जी20, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के त्रिपक्षीय संगठन - आईबीएसए और हिंद महासागर के तटों से लगे देशों के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और अंतर-सरकारी संगठन - इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे बहुपक्षीय मंचों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के पूर्ण क्षमता उपयोग पर चर्चा की और व्यवसायों और निवेशक अनुकूल वातावरण बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस संदर्भ में उपराष्ट्रपति ने प्रस्तावित भारत-दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ प्राथमिकता व्यापार समझौते का उल्लेख किया।

यूपी में अब कट्टा नहीं...मिसाइल बनती है, : सीएम योगी

कुशीनगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा का पिछली सरकारों की तरह अब यूपी में कट्टा और बम नहीं बनते, जिससे दंगे के साथ बेरोजगारी आती थी। अब नए उत्तर प्रदेश में मिसाइल बनती है, जिसके दागने पर पाकिस्तान बाप बाप करता है।

विकास के साथ रोजगार की बात होती है, अब परिवारवाद की बात नहीं होती। विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं। विकास के लिए प्रदेश के खजाने का मुंह आपकी तरफ खोल दूंगा।

कुशीनगर के तमकुहीराज में 424 करोड़ की 278 विकास परियोजनाओं का मंगलवार को लोकार्पण व शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को विकास के नाम पर पीछे ढकेलने का जिम्मेदार सीधे कांग्रेस व सपा को ठहराते हुए कुशीनगर का उदाहरण देते हुए कहा कि, वैदिक व रामायणकालीन युग की साक्षी बुद्ध व महावीर की धरती की पहचान भुखमरी व बीमारी के लिए थी। आज वह पहचान नहीं है।

अब यहां मेडिकल कालेज व कृषि विश्वविद्यालय है, जहां से डॉक्टर और विज्ञानी तैयार होंगे। यहां के जंगल पार्टी के आतंक व माफियागिरी को समाप्त करने का कार्य किया। यह केवल उदाहरण है, यह कार्य डबल इंजन सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में किया। इसका असर भी आमजन को दिख रहा है।

मुख्यमंत्री ने राम मंदिर बनने की बात करते हुए कहा कि, सपा घोषित राम द्रोही है तो कांग्रेस भी इसकी सगी है। इसलिए राम मंदिर बनने में 498 वर्ष लग गए। भाजपा की सरकार बनी तो भव्य नव्य राम मंदिर अपनी पुरानी विरासत के साथ खड़ा है।

अयोध्या अपने वैभव के साथ चमक रही है, त्रेता युग की याद दिला रही है। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों को निशाने पर लेते हुए कहा कि, उनके के पाप कृत्यों के कारण पूरा प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली व पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित था।

पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष में पूरे देश व प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है। गरीब को फ्री में राशन मिल रहा तो छत भी मिल रही है। उत्तर प्रदेश के तो पहचान का ही संकट खड़ा था।

आज वही प्रदेश चमक रहा है। कोई पर्व त्योहार बिना दंगे के नहीं मनता था, अब इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। हमने माफिया जो बेरोजगारी और मच्छर जो बीमारी देने का कार्य करते थे, दोनों को समाप्त किया। इसीलिए स्वस्थ्य उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश की राह पर है।

सीबीएसई में बड़ी कार्रवाई, ऑन-स्क्रीन मार्किंग और टेंडर विवाद के बाद चेयरमैन और सचिव की छुट्टी, जांच कमेटी गठित

(जीएनएस)।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) में पिछले कुछ समय से चल रहे ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम और टेंडर प्रक्रिया से जुड़े विवादों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों और लगातार सामने आ रही शिकायतों के बाद सरकार ने शीर्ष स्तर पर बदलाव करते हुए सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को उनके पदों से हटा दिया है।

साथ ही पूरे मामले की गहराई से जांच कराने के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मूल्यांकन प्रक्रिया, तकनीकी व्यवस्था और टेंडर से जुड़े फैसलों पर कई तरह की आपत्तियां सामने आई थीं। अब इस मामले की जांच से जुड़े निष्कर्षों पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा जगत की नजरें टिकी हुई हैं।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक टेंडर प्रक्रिया से जुड़े आरोपों और

प्रशासनिक फैसलों की जांच के लिए बनाई गई एक सदस्यीय समिति की अध्यक्षता एस. राधा चौहान करेंगी। वह वर्तमान में कैपेसिटी बिल्डिंग कमिशन की चेयरपर्सन हैं और लंबे समय तक प्रशासनिक सेवाओं में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं।

प्रशासनिक क्षेत्र का लंबा अनुभव

एस. राधा चौहान उत्तर प्रदेश कैडर की 1988 बैच की सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। वह केंद्र सरकार में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की सचिव भी रह चुकी हैं। प्रशासनिक सुधार, मानव संसाधन प्रबंधन और सुशासन के क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए सरकार ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है।

सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली पिछले कुछ महीनों से चर्चा में रही है। मूल्यांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता, तकनीकी संचालन और सिस्टम के काम करने के तरीके को लेकर अलग-अलग स्तर पर सवाल उठाए गए थे। कई लोगों ने इस प्रक्रिया में सुधार की जरूरत भी बताई थी।

'लेबनान पर चुप्पी क्यों?', पश्चिम एशिया संकट पर कांग्रेस का हमला, जयराम रमेश ने पीएम मोदी से मांगा जवाब

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लेबनान में इजराइली सैन्य कार्रवाई और अमेरिका-ईरान वार्ता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए हैं।

कांग्रेस ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः कांग्रेस ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई और अमेरिका-ईरान के बीच जारी बातचीत जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि इन घटनाक्रमों का सीधा असर भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों पर पड़ सकता है।

अमेरिका-ईरान वार्ता का किया जिक्र

जयराम रमेश ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध टालने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है। उनके मुताबिक, यदि दोनों देशों के बीच समझौता होता है तो होर्मुज स्ट्रेट के फिर से सामान्य रूप से खुलने और वैश्विक तेल कीमतों पर दबाव कम होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इन दोनों मुद्दों का भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा से गहरा संबंध है।

इजराइल की कार्रवाई बनी बाधाः कांग्रेस

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि अब तक बातचीत के अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंचने की एक बड़ी वजह लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रति नाराजगी जता चुके हैं। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि दुनिया के कई देशों ने लेबनान में इजराइल के हमलों की आलोचना की है।

प्रधानमंत्री पर साधा निशाना

अपने पोस्ट में जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इजराइल की कार्रवाई और उससे क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ रहे असर को लेकर भारत सरकार की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या तथाकथित 'फादरलैंड' उनके लिए उनकी 'मदरलैंड' से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। कांग्रेस के इस बयान के बाद पश्चिम एशिया नीति और भारत के कूटनीतिक रुख को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है।

प्रधानमंत्री ने सूरत दुर्घटना में जान गंवाने वालों के प्रति शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत जिले में हुई दुखद दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी दुर्घटनास्थल पर हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। श्री मोदी ने यह भी बताया कि इस घटना में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कियाः गुजरात के सूरत जिले में हुई दुर्घटना के बारे में सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ।

जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बचाव अभियान जारी है और अधिकारी दुर्घटनास्थल पर हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।

लखनऊ : प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में सपा नेता निकला मास्टरमाइंड, एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, परिजन बोले- एनकाउंटर हो

(जीएनएस)।

लखनऊः राजधानी लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में 27 मई को हुए प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह हत्याकांड का एसटीएफ और लखनऊ पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी का पूर्व नेता दिनेश यादव निकला। पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता दिनेश यादव और उसके ड्राइवर मुबीन को गिरफ्तार कर लिया है।

सपा नेता का राजनीतिक रसूख और खूनी साजिश

आरोपी दिनेश यादव सपा की लोहिया वाहिनी का पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुका है। सोशल मीडिया पर उसकी सपा के बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें और चुनाव प्रचार के वीडियो वायरल हो रहे हैं। पुलिस ने आरोपी की चार गाड़ियां सीज की हैं, जिनमें से एक लग्जरी कार पर 'राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लोहिया वाहिनी' का बोर्ड भी लगा हुआ है।

जांच में सामने आया है कि मूल

रूप से जौनपुर के रहने वाले संदीप सिंह और दिनेश यादव के बीच करीब पांच महीने पहले जमीन को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ था। इसी रंजिश में दिनेश ने संदीप को रास्ते से हटाने की ठान ली थी। उसने अपने ड्राइवर मुबीन के जरिए 5 लाख रुपये में भाड़े के शूटरों को संदीप की हत्या की सुपारी दी। योजना के तहत 27 मई को बाइक सवार बदमाशों ने संदीप की गोली मारकर हत्या कर दी।

परिजनों की मांग- 'हो गाजियाबाद जैसा एनकाउंटर'

हत्याकांड के खुलासे के बाद मृतक संदीप सिंह के परिजन पीजीआई थाने पहुंचे और पुलिस कमिश्नर व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। परिजनों ने मांग की है कि जिस तरह गाजियाबाद की घटना में हत्यारों का एनकाउंटर किया गया, उसी तरह संदीप के हत्यारे शूटरों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। परिजनों का कहना है कि संदीप बेहद सीधा और सरल व्यक्ति था। अब इस खूंखार गैंग से उनके परिवार की जान को भी खतरा है, इसलिए उन्हें तत्काल पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए।

रोहित शर्मा को बीसीसीआई से मिला सख्त अल्टीमेटम, अफगानिस्तान के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेलने पर लटकी तलवार

भारतीय क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान के बीच होने वाली आगामी वनडे सीरीज से पहले खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस घरेलू सीरीज के लिए टीम का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन दो सीनियर खिलाड़ियों की भागीदारी पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है।

रिपोर्ट्स के अनुसार चयनकताओं ने साफ किया है कि टीम में शामिल होने के बावजूद कुछ सीनियर नामों को मैदान पर उतरने से पहले अपनी शारीरिक फिटनेस साबित करनी होगी।

असम के कृषि और ग्रामीण विकास के लिए फंड की कोई कमी नहीं होगी, केंद्र का रहेगा पूरा सहयोगः श्री शिवराज सिंह चौहान

(जीएनएस)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा ने नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में राज्य से संबंधित विषयों पर बैठक की। इस उच्च स्तरीय बैठक में असम में कृषि और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा कई महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई।

बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में असम के कृषि और ग्रामीण विकास के लिए फंड और संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने राज्य को कृषि अवसंरचना कोष (AIF), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G), मनरेगा तथा अन्य केंद्रीय योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के एजेंडे पर सचिव श्री रोहित कंसल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) और मनरेगा प्रणाली की तकनीकी बाधाओं को पूरी तरह दूर कर दिया गया है। मनरेगा के तहत असम सरकार की मांग के अनुरूप राशि आवंटित की जा चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी 1 जुलाई से देशभर में मनरेगा की जगह विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) लागू किया जाएगा।

बैठक में असम सरकार द्वारा चाय बागान (टी-गार्डन) श्रमिकों को भूमि

का मालिकाना हक (पट्टा) प्रदान किए जाने के ऐतिहासिक कदम की सराहना की गई। केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिए कि इन श्रमिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार एक विशेष सर्वे विंडो खोलेगी, ताकि पात्र लाभार्थियों के नाम डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज किए जा सकें।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने असम की विशिष्ट जलवायु और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर तैयार कृषि कार्ययोजना का प्रारूप मुख्यमंत्री श्री सरमा को सौंपा। बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर सहमति बनी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में असम ने लक्ष्य से अधिक 9 लाख से ज्यादा 'लखपति दीदी' तैयार कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।

20.39 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण: बोले सीएम योगी, ताल-पोखरों को बपौती समझते थे लोग, अब बनता है पर्यटन स्थल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिलुआताल में 20.39 करोड़ रुपये की पर्यटन परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने तालाबों के संरक्षण, इको टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स, सोलर प्लांट और स्वच्छता पर जोर देते हुए चिलुआताल को रामगढ़ताल की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की।

(जीएनएस)।

गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिलुआताल में 20.39 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटन विकास से संबंधित निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ताल में प्राकृतिक जल है, लेकिन वहां शहर के पानी को ट्रीट कर छोड़ा जाता है। चिलुआताल में भी प्राकृतिक जल है और इसका शुद्धिकरण किया गया है। पिछली सरकारों में ताल और पोखरों पर अतिक्रमण किया जाता था। उन्हें नष्ट किया जाता था। लोग उन्हें अपनी बपौती समझकर कब्जा कर लेते थे और हवेलियां बना लेते थे। ऐसे क्षेत्र गंदगी और अपराध के गढ़ बन जाते थे। अब डबल इंजन वाली सरकार ताल और पोखरों का संरक्षण कर रही है।

'चिलुआताल में वाटर स्पोर्ट्स की अपार संभावनाएं'

सीएम योगी ने कहा कि पिछले दिनों रामगढ़ताल में नेशनल रोइंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इसमें 22 राज्यों के 243 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। सभी प्रतिभागी कहते थे कि इतनी अच्छी झील देखने को कम ही मिलती है। वे लोग यहां आएंगे तो उन्हें और अच्छा लगेगा। रामगढ़ताल के साथ चिलुआताल में भी वाटर स्पोर्ट्स की अपार संभावनाएं हैं। यहां दुकानें खुल गई हैं। लोग परिवार के साथ आकर यहां घूम सकते हैं। यहां न प्रदूषण है और न किसी प्रकार की अव्यवस्था। यहां का तापमान भी शहर की तुलना में कम रहता है। पूरी झील से आने वाली ठंडी हवा तापमान को कम बनाए रखती है।

रामगढ़ताल की तर्ज पर किया जाएगा विकसित

यही सिटी डेवलपमेंट प्लान होता है। अब हमारी सिटी केवल स्मार्ट ही नहीं, बल्कि सेफ और सस्टेनेबल सिटी के रूप में भी आगे बढ़ रही है। फर्टिलाइजर प्लांट छह वर्ष पहले तक बंद था। वर्ष 1990 से 2021 तक इसकी गतिविधियां ठप थीं। बीच के समय में यहां एसएसबी आ गई, अन्यथा यहां का स्क्रैप भी गायब हो गया होता। अब यहां एसएसबी, फर्टिलाइजर प्लांट, सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय भी हैं। केंद्रीय विद्यालय के नए भवन के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। जब प्रधानमंत्री ने इस फर्टिलाइजर प्लांट का शुभारंभ किया था, तभी इस वाटर बॉडी को विकसित करने का विचार आया था। फर्टिलाइजर प्लांट को जल की आवश्यकता थी। इसे रामगढ़ताल की तर्ज पर विकसित कर इको टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स का हब बनाया जाएगा।

गंदगी न फैलाने की अपील

यहां एक सोलर प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है। 20 मेगावाट क्षमता के इस प्लांट से पूरे शहर को बिजली मिलेगी। यह ग्रीन एनर्जी का स्रोत होगा। डबल इंजन की सरकार विकास कार्य कर सकती है। शहरवासियों की भी जिम्मेदारी है कि वे इसे संरक्षित करें। गंदगी न फैलाएं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। यदि कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसकी शिकायत करें, ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। रामगढ़ताल में हाल ही में सफाई अभियान चलाया गया था, जिसमें 56 बोरे कचरा निकला। 5 से 21 जून के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में विशेष अभियान चलाया जाएगा। चिलुआताल और रामगढ़ताल के आसपास पौधरोपण किया जाए। 4 जून को गंदगी के खिलाफ अभियान चलाकर सफाई की जाए।

मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि रवि किशन उम्र को लेकर मजाक करते हैं, लेकिन उन्हें बता दें कि उनके सामने हम जेन-जी हैं, नेपाल और बांग्लादेश वाले नहीं।

दोस्ती, छुरेबाजी और नसीहत! सीएम योगी ने खींच दी यूपी चुनाव की लकीर, अपराध पर जीरो टॉलरेंस

गाजियाबाद में बकरीद के मौके पर एक हिंदू युवक सूर्या चौहान की बेरहमी से हत्या और उसके बाद शुरू हुई पुलिस कार्रवाई पर विधानसभा चुनाव की बिसात बिछती दिख रही है। योगी सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति को यूं ही नहीं धार दे रही है।

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरूआत में विधानसभा चुनाव होना है। लखनऊ के सियासी गलियारों और मीडिया बंधुओं के बीच इसे समय से कुछ महीने पहले करवाए जाने की अटकलबाजियां भी चलने लगी हैं। इन सबके बीच गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में सूर्या चौहान हत्याकांड के आरोपियों पर जिस तरह से यूपी पुलिस ने कार्रवाई की है और कर रही है, वह प्रदेश में चुनावी टोन सेट करने का एक बड़ा आधार बनता दिख रहा है।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे भारत में अपनी छवि अपराध से मुक्ति दिलाने वाले सीएम के तौर पर बनाई है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, पिछले 9 वर्षों से ज्यादा के उनके शासन काल में जिस तरह से दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, वह आम जनता को पसंद आता है, यह कहने में निष्पक्ष से निष्पक्ष व्यक्ति को भी कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। गाजियाबाद का सूर्या चौहान हत्याकांड उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है।

अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बड़ा एजेंडा

सूर्या चौहान की बेरहमी से हत्या के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया।

इस हत्याकांड के तीन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और आरोपियों के अवैध निमार्णों पर बुलडोजर चलने की भी तैयारी है।

यूपी में अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हाल के वर्षों में नई नहीं है।

लेकिन, सूर्या चौहान का कत्ल और उसके कातिल दोस्त का त्वरित एनकाउंटर कई मायनों में इस संवेदनशील राज्य के लिए अहम है।

असद पर आरोप था कि उसने अपने दोस्त को बकरीद के मौके पर मिलने के लिए बुलाया और उसी की बकरे की तरह कुर्बानी दे दी।

यह घटना सिर्फ हृदयविदारक नहीं है, इंसानियत की दुनिया के लिए बहुत ही असमान्य और रूह कंपा देने वाला हत्याकांड है।

फिर भी समाज का एक वर्ग इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने की कोशिश से बाज नहीं आ रहा और इसी के चलते यह मसला बहुत बड़ा चुनावी एजेंडा बनता दिख रहा है।

'दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं'

सोमवार (1 जून,2026) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में इस मुद्दे को उठाते हुए एक बार फिर से, लेकिन बहुत ही कड़े अंजाद में चेतावनी दे दी है। मुख्यमंत्री ने ऐसे जघन्य अपराध और उन्हें अंजाम देने वाले अपराधियों से दो टूक कह दिया है- 'दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं।...जो अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है, वह गलती कर रहा है।'

एनकाउंटर पर सवाल तो किसे फायदा

सूर्या चौहान एक हिंदू युवक था। आरोप है कि उसके मुस्लिम दोस्त असद ने बकरीद के दिन बेरहमी से तड़पा-तड़पा कर मार डाल और वह भी बकरे की कुर्बानी दिखाने के नाम पर। यह भी आरोप है कि ऐसे हत्यारे के एनकाउंटर पर इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि वह मुस्लिम था। ऐसे में यूं कह लें कि बीजेपी को उसी के पिच पर ऐसे बॉल फेंके जा रहे हैं, जिन्हें बाउंडरी के बाहर पहुंचाने में उसे महारत हासिल है।

बंगाल और असम में बीजेपी को मिला लाभ

बीजेपी अभी-अभी असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव जीती है। बहुत ही शानदार तरीके से जीती है। वहां भी सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ओर से जमकर हिंदू-मुस्लिम को मुद्दा बनाया गया। फायदे में बीजेपी रही। फिर भी वहां एक मुस्लिम विधायक ने बकरीद के मौके पर गाय को लेकर भड़काऊ बयान दिया और उसकी सियासी तपिश यूपी में शुरू हो गई।

'गोमाता राष्ट्रमाता हैं.. आक्रांता हमें न बताए'

बकरीद से पहले यूपी में कुछ मुसलमानों ने यह बयान देना शुरू कर दिया कि अगर गौहत्या हिंदुओं की आस्था पर हमला है तो इसे रोकने के लिए इसे राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर दिया जाता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसपर भी अपनी लाइन स्पष्ट कर दी है।

भड़काऊ टिप्पणी करने वालों को चेतावनी

यूपी में कुछ मुस्लिम नेताओं ने बकरीद पर गाय की कुर्बानी का सख्त विरोध किया, लेकिन फिर भी कुछ सोशल मीडिया हैंडलों से माहौल बिगाड़ने की भरपूर कोशिशें की गईं। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने मौलानाओं से कहा, 'गोमाता के साथ हिमाकत करने वाले चेलों को समझाएं, वरना ऐसी दुर्गति होगी कि कई पीढ़ियां याद करेंगी।'

कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरना मुश्किल

सीएम योगी से लाइन मिलते ही डीजीपी राजीव कृष्ण ने भी अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कहकर स्पष्ट कर दिया कि किसी भी तरह के अपराधियों से पुलिस आगे कैसे निपटने वाली है। अगर इस नीति को 2027 के विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो-

बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर रत्ती भर समझौता नहीं करने जा रही।

सीएम योगी की सरकार की जो अपराध-विरोधी छवि बनी हुई है, उससे पार्टी टस से मस नहीं होगी।

कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष के लिए सरकार को घेरना बहुत ही मुश्किल होगा, जो कि आम जनता की प्राथमिकताओं में सबसे आगे है।

लखनऊ में सैन्यकर्मी पर महिला को पांच साल बंधक बनाकर दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन दबाव का आरोप, जांच जारी

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला ने एक सैन्यकर्मी पर पांच वर्षों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

लखनऊ, 2 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला ने एक सैन्यकर्मी पर पांच वर्षों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, सैरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला की शिकायत पर 30 मई को सैन्यकर्मी मंजूर अली, उसके भाई कमाल और रिश्तेदार सलमान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और सोमवार को मुख्य आरोपी मंजूर अली को गिरफ्तार कर लिया।

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसका विवाह सीतापुर जिले में हुआ था। मार्च 2021 में वह अपने मायके सैरपुर स्थित घर आई थी। महिला का आरोप है कि इसी दौरान लखीमपुर खीरी जिले के महंगूखेड़ा निवासी मंजूर अली ने देर रात उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर अगवा कर लिया। शिकायत के अनुसार, इसके बाद आरोपी ने उसे विभिन्न स्थानों पर बंधक बनाकर रखा और लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।

महिला का आरोप है कि आरोपी उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर छिपाकर रखता था, ताकि वह किसी से संपर्क न कर सके। उसने यह भी आरोप लगाया कि मंजूर अली उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था। विरोध करने पर उसे डराया-धमकाया जाता था।

एफआईआर के अनुसार, जब मंजूर अली ड्यूटी पर जाता था, तब वह महिला को अपने भाई कमाल और रिश्तेदार सलमान के पास छोड़ देता था। पीड़िता का आरोप है कि दोनों उसे जान से मारने की धमकी देकर छिपाकर रखते थे और किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क नहीं करने देते थे।

महिला के अनुसार, कुछ दिन पहले उसे एक पड़ोसी की मदद से अपने पिता से फोन पर संपर्क करने का अवसर मिला। सूचना मिलने पर उसके पिता बताए गए पते पर पहुंचे और उसे वहां से लेकर सैरपुर स्थित अपने घर वापस ले आए। इसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क कर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच की जा रही है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य नामजद आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस के अनुसार, जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ में यार्ड ब्लॉक, भोपाल मंडल की 4 ट्रेनें प्रभावित, लखनऊ रूट के यात्रियों को होगी परेशानी

(जीएनएस)।

भोपाल , लखनऊ मंडल में यार्ड ब्लॉक के कारण भोपाल मंडल से गुजरने वाली चार प्रमुख ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। दो ट्रेनों का आंशिक निरस्तीकरण किया गया है, जबकि दो ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी है।

उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में चल रहे यार्ड ब्लॉक का असर अब भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली ट्रेनों पर भी दिखाई देने लगा है। रेलवे ने चार महत्वपूर्ण ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है। इनमें कुछ ट्रेनों का मार्ग बदला गया है तो कुछ को गंतव्य स्टेशन से पहले ही समाप्त किया जाएगा। इससे हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।

लखनऊ तक नहीं पहुंचेगी यशवंतपुर-लखनऊ एक्सप्रेस

रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 22683 यशवंतपुर-लखनऊ एक्सप्रेस 1 जून को अपने निर्धारित गंतव्य लखनऊ तक नहीं जाएगी। यह ट्रेन उतरेटिया स्टेशन पर ही समाप्त कर दी जाएगी। वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 22684 लखनऊ-यशवंतपुर एक्सप्रेस 4 जून को लखनऊ के बजाय उतरेटिया स्टेशन से ही रवाना होगी।

दो ट्रेनों का बदला मार्ग

यार्ड ब्लॉक के कारण गाड़ी संख्या 15066 पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस का मार्ग भी बदला गया है। यह ट्रेन 1 से 3 जून तक अपने नियमित मार्ग मानक नगर-लखनऊ-मल्हौर के बजाय मानक नगर-ऐशबाग-मल्हौर होकर संचालित होगी। इस दौरान ट्रेन लखनऊ स्टेशन नहीं जाएगी और उसकी जगह ऐशबाग तथा बादशाह नगर स्टेशन पर ठहराव रहेगा। वहीं गाड़ी संख्या 12173 लोकमान्य तिलक टर्मिनल-प्रतापगढ़ एक्सप्रेस 2 जून को कानपुर सेंट्रल-लखनऊ-रायबरेली-प्रतापगढ़ मार्ग के बजाय कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज-फाफामऊ-प्रतापगढ़ होकर चलेगी। इसके चलते ट्रेन लखनऊ, रायबरेली और अमेठी स्टेशन नहीं पहुंचेगी। यात्रियों को प्रयागराज स्टेशन से वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

यात्रा से पहले जांच लें ट्रेन की स्थिति

रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की ताजा स्थिति अवश्य जांच लें। यार्ड ब्लॉक के चलते अंतिम समय में भी परिचालन संबंधी बदलाव संभव हैं। यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 या एनटीईएस के माध्यम से अपनी ट्रेन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

क्या है अमेरिका की धारा 301? जिस पर भारत मांग रहा गारंटी, दिल्ली ने खेला मास्टरस्ट्रोक!

(जीएनएस)।

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित Trade Deal को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जिसमें भारत की शर्त ने डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। दोनों देशों के अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे हैं और समझौते के मसौदे पर काम जारी है। हालांकि, नई दिल्ली चाहती है कि भविष्य में अमेरिका ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे इस समझौते के तहत मिलने वाले फायदे कमजोर पड़ जाएं। खासतौर पर भारत की चिंता अमेरिकी ट्रेड कानून की धारा 301 (Section 301) को लेकर है। जानेंगे क्या है धारा 301 और क्या है शर्त।

टैरिफ रद्द होने के बाद बदली अमेरिका की नीति

इस साल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए कुछ जवाबी टैरिफ को रद्द कर दिया था। ये टैरिफ International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) के तहत लगाए गए थे। अदालती फैसले के बाद अमेरिका ने व्यापारिक कार्रवाई के लिए दूसरे कानूनी विकल्पों पर ध्यान देना शुरू किया। इनमें सबसे अहम है TrÔde Act 1974 की Section 301, जो अमेरिका को विदेशी व्यापारिक नीतियों की जांच करने और जरूरत पड़ने पर सीधे जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार देती है।

भारत समेत कई देशों पर चल रही है जांच

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने इस समय कई देशों के खिलाफ Section 301 के तहत जांच शुरू कर रखी है। इस सूची में भारत, चीन, जापान, यूरोपीय संघ, सिंगापुर समेत कई देश शामिल हैं। इन जांचों का असर भारत के कुछ सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज पर पड़ सकता है। यही वजह है कि इंडियन इंडस्ट्री और सरकार दोनों इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं।

नई दिल्ली पहुंचे अमेरिकी ट्रेड सेक्रेटरी

सोमवार को दक्षिण और मध्य एशिया के लिए डिप्टी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेंडन लिंच के अगुवाई में एक अमेरिकी डेलिगेशन नई दिल्ली पहुंचा। उनका यह दौरा भारत-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट पर चल रही बातचीत के नए दौर की शुरूआत माना जा रहा है। दोनों पक्ष व्यापारिक मतभेदों को कम करने की कोशिश में जुटे हैं।

भारत को Section 301 से क्यों है चिंता?

भारत और अमेरिका फरवरी 2026 से व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से दोनों देशों के अधिकारी टैरिफ, बाजार तक पहुंच और रेगुलेटर बाधाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं।

लेकिन ट्रंप प्रशासन के पुराने टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद अमेरिका का ध्यान Section 301 की तरफ चला गया। भारत को डर है कि अगर व्यापार समझौते के तहत वह अमेरिकी वस्तुओं को छूट देता है और बाद में अमेरिका Section 301 के जरिए भारतीय उत्पादों पर नए टैरिफ लगा देता है, तो भारत को दोहरा नुकसान हो सकता है।

भारत की क्या है मांग?

भारतीय रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं कि एग्रीमेंट को फाइन करने से पहले अमेरिका टैरिफ को लेकर स्पष्ट आश्वासन दे। बातचीत से जुड़े एक भारतीय सूत्र ने रॉयटर्स से कहा, "भारत को टैरिफ दर, Section 301 जांच के प्रभाव और कॉम्प्टीटिव टैरिफ अरेंजमेंट्स पर चर्चा करनी होगी।" सूत्र ने यह भी कहा कि यदि शर्तें ट्रांसपेरेंट, बैलेंस और जस्टिफाइड होती हैं तो समझौता जल्द पूरा हो सकता है।

आखिर क्या है Section 301?

Trade Act 1974 की Section 301 अमेरिकन ट्रेड सेक्रेटरी ऑफिस को यह अधिकार देती है कि वह किसी भी विदेशी देश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जांच करे यदि उसे लगता है कि वे अमेरिकी व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचा रही हैं। यदि जांच में अमेरिकी प्रशासन को लगता है कि कोई देश अनुचित व्यापारिक रवैया अपना रहा है, तो अमेरिका अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है, इम्पोर्ट में कमी ला सकता है या पहले दी गई व्यापारिक रियायतें वापस ले सकता है।

किन कारणों से शुरू होती है Section 301 जांच?

Section 301 जांच कई कारणों से शुरू हो सकती है। इनमें इंटेलेक्चुअल कॉपी राइट, जबरन टेक्नोलॉडी ट्रांसफर, लेबल लॉ का उल्लंघन, विदेशी बाजारों में पहुंच की बाधाएं, भेदभावपूर्ण नियम और सरकारी सब्सिडी जैसे मुद्दे शामिल हैं। यही वजह है कि इसे अमेरिका के सबसे शक्तिशाली व्यापारिक हथियारों में से एक माना जाता है।

WTO से अलग क्यों है Section 301?

विश्व व्यापार संगठन (WTO) में किसी विवाद को सुलझाने के लिए लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। लेकिन Section 301 के तहत अमेरिका खुद जांच करता है, खुद फैसला लेता है और जरूरत पड़ने पर खुद ही कार्रवाई भी कर सकता है। यही कारण है कि कई देश इसे एकतरफा व्यापारिक दबाव का टूल मानते हैं।

ट्रंप के दौर में फिर चर्चा में आया कानून

1980 के दशक में यह कानून काफी इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि WTO बनने के बाद इसका उपयोग कम हो गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में चीन पर लगाए गए भारी टैरिफ का कानूनी आधार भी यही Section 301 था। अब IEEPA टैरिफ को कानूनी झटका मिलने के बाद यह कानून फिर से अमेरिकी व्यापार नीति का अहम हिस्सा बन गया है।

अमेरिका में 320,000,000 मच्छर क्यों छोड़ रहा गूगल? डेंगू रोकने का प्लान या फैलाने का?

(जीएनएस)।

मच्छर आमतौर पर लोगों के लिए परेशानी की वजह बनते हैं, लेकिन अब Google एक ऐसा प्लान लेकर आया है जिसमें वह खुद करोड़ों मच्छरों को खुले में छोड़ना चाहता है। सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन कंपनी का दावा है कि इससे डेंगू, जीका, चिकनगुनिया और वेस्ट नाइल वायरस जैसी खतरनाक बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है।

इसी वजह से Google ने अमेरिका के कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा राज्यों में कुल 3.2 करोड़ खास नस्ल के मच्छर छोड़ने की परमीशन मांगी है। यह पहल दुनिया भर में बढ़ रही मच्छर जनित बीमारियों से निपटने की कोशिशों का हिस्सा मानी जा रही है।

एडअ कर रही है प्रस्ताव की जांच

इस समय अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) Google की मच्छर नियंत्रण प्रोजेक्ट "Debug" से जुड़े प्रस्ताव की जांच कर रही है। फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित नोटिस के मुताबिक, इस योजना के तहत दो साल तक हर साल 1.6 करोड़ मच्छर छोड़े जाएंगे। यानी दो साल में कुल 3.2 करोड़ मच्छरों को खुले वातावरण में छोड़ा जा सकता है। इस प्रस्ताव पर 5 जून तक सार्वजनिक सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके बाद एढअ अंतिम फैसला लेगी कि इस योजना को मंजूरी दी जाए या नहीं।

आखिर कौन से मच्छर छोड़े जाएंगे?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि Google आखिर किस तरह के मच्छर छोड़ना चाहता है? यह प्रोजेक्ट "Wolbachia" नामक एक प्राकृतिक बैक्टीरिया पर आधारित है। वैज्ञानिक इस बैक्टीरिया से संक्रमित नर मच्छरों को तैयार करते हैं और फिर उन्हें खुले वातावरण में छोड़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नर मच्छर इंसानों को काटते नहीं हैं और न ही किसी तरह की बीमारी फैलाते हैं। इसलिए इनसे सीधे तौर पर लोगों को कोई खतरा नहीं होता।

जब ये Wolbachia-संक्रमित नर मच्छर सामान्य मादा मच्छरों के साथ प्रजनन करते हैं, तो उनसे पैदा होने वाले अंडों से ऐसा मच्छर या यूं कहें की मच्छरों की अगली जनरेशन पैदा होती है जो किसी काम की नहीं होती। न ये आगे प्रजनन कर पाते हैं और न ही किसी को काट सकते हैं।। इसका असर यह होता है कि समय के साथ मच्छरों की नई पीढ़ियां कम होती जाती हैं। लगातार कई पीढ़ियों तक यह प्रक्रिया चलने पर मच्छरों की कुल आबादी तेजी से घटने लगती है। यानी यह तकनीक मच्छरों को मारने की बजाय उनकी संख्या को प्राकृतिक तरीके से कम करने पर काम करती है।

यह पूरा कार्यक्रम Google की मूल कंपनी Alphabet के लाइफ साइंस और टेक्नोलॉजी डिवीजन द्वारा डेवलप किया गया है। इस प्रोजेक्ट का फोकस खास तौर पर Aedes aegypt प्रजाति के मच्छरों पर है। यही वह मच्छर है जो डेंगू, जीका वायरस, चिकनगुनिया और Yellow Fever जैसी गंभीर बीमारियों को फैलाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। दुनिया के कई देशों में डेंगू और जीका के बढ़ते मामलों के पीछे इसी मच्छर की बड़ी भूमिका रही है।

Debug Program सिर्फ मच्छर छोड़ने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा टेक्नोलॉजी नेटवर्क काम करता है। Google की टीम बायोटेक्नोलॉजी, एडवांस ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से लाखों नर मच्छरों का उत्पादन, उनकी छंटाई और वितरण करती है। कंपनी का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में मच्छरों को तैयार करना और सही जगहों तक पहुंचाना बिना आधुनिक तकनीक के संभव नहीं है।

PRGI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

कमजोर मानसून के हालात

मौसम विभाग द्वारा 29 मई को जून से सितंबर मानसून के दौरान 10 प्रतिशत कम बरसात का पूवार्नुमान बेहद चिताजनक का कारण बन गया है। इससे पहले जारी पूवार्नुमान में 8 प्रतिशत कम बरसात की संभावना व्यक्त की गई थी। लगभग दस साल बाद देश में कमजोर मानसून के हालात रहने की संभावना है। अर्थव्यवस्था के लिए यह इसलिए और भी अधिक चितनीय हो जाता है कि एक और अमेरिका- इजरायल और ईरान के बीच सीजफायर के आसार नहीं दिख रहे हैं और इसके कारण भारत सहित दुनिया के अधिकांश देश कच्चे तेल और गैस की समस्या से दो चार हो रहे हैं और इसका सीधा असर महंगाई बढ़ना हो रहा है। दूसरी और अब अलनीनों के प्रभाव से इस साल कमजोर मानसून के कारण 10 प्रतिशत कम बरसात होने से हालात और भी गंभीर होने की संभावना बनती जा रही है। करीब दस साल बाद ऐसे हालात बनने जा रहे हैं। खास बात यह है कि उत्तर पूर्व को छोड़कर समूचे देश में कम बरसात की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के पूवार्नुमान को इसलिए भी नहीं नकारा जा सकता है कि पिछले सालों में भारतीय मौसम विभाग के पूवार्नुमान लगभग सटीक रहने लगे हैं। मजे की बात यह है कि इस साल गमा भी भीषण पड़ रही है और पिछले एक माह में ही जलाशयों में उपलब्ध पानी में तेजी से कमी आई है। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश के प्रमुख 166 जलाशयों में वुल भराव क्षमता का 24 प्रतिशत के आसपास ही पानी रह गया है और तेजी से पानी कम होता जा रहा है। दक्षिण भारत के हालात अधिक गंभीर है और वहां लगभग 17 प्रतिशत ही पानी रह गया है। उत्तरी भारत के जलाशयों में 26 तो पिमी भारत के जलाशयों में 28 प्रतिशत के आसपास ही पानी रह गया है। मानसून भी तय समय से बिलंबित हो रहा है। एक बात साफ हो जानी चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था मानसूनी बरसात पर बहुत वुछ निर्भर करती है। देश में मानसून सीजन में 87 सेमी बरसात होती है। पूवार्नुमानों को माने तो 2018 में 91 प्रतिशत बरसात हुई थी उसके बाद के सालों में मानसून लगभग अच्छा ही रहा है। पिछले सालों में मानसून की स्थिति देखें तो 2023 में मानसून अवश्य कमजोर रहा है अन्यथा देश में मानसूनी वर्षा 100 प्रतिशत के आसापास व इससे अधिक ही रही है।

कमजोर मानसून के कारण भूजल स्तर में गिरावट, अधिक पानी पर निर्भर धान, तिलहन और दलहन की फसल प्रभावित होगी और इस कारण से खाद्य महंगाई बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इससे आम आदमी की थाली पर असर पड़ेगा और सब्जी, दाल और अनाज सभी के भाव बढ़ने का असर दिखाई देगा। इसी तरह से देश के अनेक हिस्सों में पीने के पानी की दिक्कत आम है। बांधों में तेजी से पानी की कमी और मानसून कमजोर रहने से पानी की कम आवक रहती है तो निति रुप से सिचाई व पेयजल दोनों के लिए पानी की दिक्कत होगी। जल विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन पर असर होगा तो वुल मिलाकर अर्थ व्यवस्था को प्रभावित होने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल देश में एक समय था जब सूखा आम होता था और व्यापक स्तर पर अकाल राहत कार्य संचालित होते थे।

हांलाकि देश के हालातों में काफी सुधार हुआ है और अकाल को तो लगभग भूल ही चुके हैं। पर सवाल वहीं का वहीं है कि जल संचयन के जो प्रयास होने चाहिए थे और उनका जिस तरह का प्रभाव पड़ना चाहिए था वह अभी तक सामने नहीं आया है। सरकार के सामने कमजोर मानसून के हालात से निपटने की बड़ी चुनौती आने वाली है। सबसे अधिक तो जल संग्रहण की चुनौती होगी क्योंकि प्रावृतिक जल संग्रहण के रास्ते शहरीकरण की भेंट चढ़ चुके हैं। दीर्घकालीन सोच के साथ ठोस प्रयास नहीं होने से बरसात के पानी का सही तरीके से संग्रहण भी नहीं हो पा रहा है। जितने पानी की साल भर आवश्यकता होती है उससे अधिक बरसाती पानी तो बह जाता है। इसके अलावा पानी का उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही बढ़ गए हैं।

इबोला से डरे अफ्रीका में हाहाकार के बीच भारत ने बॉक्स में ऐसा क्या भेजा, दुनिया कर रही तारीफ

अमेरिका और ईरान में टकराव थमता नहीं दिख रहा है। मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत ने एक बार फिर ऐसा कदम उठाया जिसकी तारीफ कई देश कर रहे हैं। दरअसल, इबोला संकट से जूझ रहे अफ्रीका को भारत ने लगातार दूसरी बार मेडिकल सपोर्ट भेजा है। जयशंकर ने इस संबंध में ट्वीट भी किया है।

नई दिल्लीः कोरोना महामारी के बाद अब इबोला का कहर कई देशों की टेंशन बढ़ा रहा है। खास तौर से अफ्रीका में इबोला के प्रकोप से हाहाकार मचा हुआ है। इस मुश्किल घड़ी में भारत ने एक बार फिर ऐसा कदम उठाया, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ किए बिना नहीं रह सकती। भारत ने इबोला संकट से जूझ रहे पूरे अफ्रीका में मेडिकल समेत कई जरूरी सपोर्ट भेजा है। ये पहली बार नहीं है जब नरेंद्र मोदी सरकार ने ये कदम उठाया है। भारत ने अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (अफ्रीका सीडीसी) को 43 टन मेडिकल सहायता की खेप भेजी है। दिल्ली से अफ्रीका में भेजी गई मदद की ये दूसरी किस्त है।

जयशंकर ने शेयर की खास तस्वीरें

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अफ्रीका सीडीसी को भेजे गए मेडिकल सपोर्ट जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर की है। जयशंकर ने बताया कि इस मेडिकल सहायता में प्रोटेक्टिव गियर, डायग्नोस्टिक और मॉनिटरिंग उपकरण, दवाएं और सप्लीमेंट्स शामिल हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि यह 43 टन की दूसरी खेप अफ्रीका में सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को और मजबूत करेगी। इसके साथ ही अफ्रीका यूनियन में इबोला संकट से निपटने में अहम रेस्पॉन्स क्षमताओं को बढ़ाएगी।

भारत की मदद का अफ्रीका ने किया स्वागत

इससे पहले सोमवार को, अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (आ१ूं उऊ) ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (अ्फ्ठ) के पूर्वी क्षेत्रों में चल रहे इबोला रेस्पॉन्स प्रयासों में सपोर्ट के लिए भारत की मदद का स्वागत किया था। उन्होंने इबोला की रोकथाम में जरूरी मदद के लिए भारत सरकार की ओर से प्रदान किए गए इमरजेंसी सपोर्ट, इलाज और मेडिकल आपूर्ति की तारीफ की थी। इसने पर एक पोस्ट में कहा कि यह आपूर्ति युगांडा में आ१ूं उऊ के पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से पहुंचाई गई थी और पूर्वी अ्फ्ठ में प्रतिक्रिया प्रयासों का समर्थन करने के लिए भेजी गई थी।

इबोला से जूझ रहे कई अफ्रीकी देश

इस महाद्वीपीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने आगे कहा कि यह सहायता इबोला प्रकोप को नियंत्रित करने और प्रभावित समुदायों का समर्थन करने के चल रहे प्रयासों को मजबूत करेगी। इसने भारत की ओर से लगातार जारी समर्थन के प्रति भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम अफ्रीका के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भारत सरकार और भारत की जनता को धन्यवाद देते हैं।

अफ्रीका सीडीसी ने भारत के मदद पर दिया ये रिएक्शन

अफ्रीका सीडीसी, जो अफ्रीकी संघ की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी है।

ये पूरे महाद्वीप में बीमारी की रोकथाम और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इससे पहले 29 मई को, भारत ने आधिकारिक तौर पर अफ्रीका को आपातकालीन मेडिकल आपूर्ति की अपनी पहली खेप भेजने की पुष्टि की थी।

इससे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) में बिगड़ते बुंडिबुग्यो इबोला प्रकोप से निपटने में सहायता मिल सके।

नई दिल्ली ने दोहराया है कि वह अफ्रीकी स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और जैसे-जैसे स्थिति बदलेगी, वह मेडिकल और रसद सहायता की अगली किस्त भी भेजने के लिए तैयार है।

पीएम मोदी और सीएम भजनलाल की ढाई घंटे की बैठक के क्या हैं मायने? कैबिनेट में जल्द हो सकता है फेरबदल!

(जीएनएस)।

जयपुर , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की लंबी बैठक के बाद राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि आगामी निकाय और पंचायत चुनावों से पहले भाजपा सरकार और संगठन स्तर पर कुछ बड़े फैसले ले सकती है।

नियुक्तियों की चचाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि निकाय और पंचायत चुनावों से पहले भाजपा संगठन और सरकार स्तर पर महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच हुई करीब ढाई घंटे की महत्वपूर्ण बैठक के बाद राजस्थान की राजनीति में नई चचाओं ने जोर पकड़ लिया है। राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार और लंबित राजनीतिक

20 जून से पहले मोदी कैबिनेट का विस्तार संभवः 10 जून को मुख्यमंत्री परिषद की बैठक; ये दो मंत्री देंगे इस्तीफा

सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान प्रदेश सरकार के कामकाज, संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार और विभिन्न बोर्ड, निगम, आयोग तथा सरकारी संस्थानों में लंबे समय से लंबित राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी मंथन किए जाने की चर्चा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी वर्ष को देखते हुए भाजपा सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की दिशा में कदम उठा सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने पर विचार किया जा सकता है। वहीं, राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से संगठन से जुड़े नेताओं और कार्यकताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपे जाने की संभावना भी जताई जा रही है।

संगठन को मजबूती मिलेगी

प्रदेश भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता लंबे समय से बोर्ड, निगम और आयोगों में नियुक्तियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में यदि सरकार इन नियुक्तियों पर फैसला करती है तो इससे संगठन को मजबूती मिलने के साथ-साथ कार्यकताओं में भी सकारात्मक संदेश जाएगा।हालांकि, मुख्यमंत्री के नेतृत्व को लेकर किसी प्रकार के बदलाव की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। भाजपा नेतृत्व पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि राजस्थान में सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ही कार्य करती रहेगी। पार्टी का फोकस विकास कार्यों, सुशासन और आगामी चुनावी तैयारियों पर बना हुआ है।

अब राजनीतिक हलकों की नजर भाजपा नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी हुई है। यदि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कोई घोषणा होती है, तो इसे आगामी निकाय और पंचायत चुनावों की रणनीतिक तैयारी के रूप में देखा जाएगा।

डोंबिवली के पिंपलेश्वर महादेव मंदिर की क्या है खासियत? 20 साल की लड़ाई के बाद मिली जीत, होगा भव्य शिवोत्सव

(जीएनएस)।

महाराष्ट्र के डोंबिवली के प्रसिद्ध पिंपलेश्वर महादेव मंदिर इन दिनों सुर्खियों में है। क्योंकि इस मंदिर से जुड़ा करीब दो दशक पुराना भूमि विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार की ओर से मंदिर को 4 एकड़ 25 गुंठा जमीन देवस्थान के अधिकार में देने के फैसले के बाद पूरे इलाके में उत्सव जैसा माहौल है। श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक इस निर्णय को आस्था और संघर्ष की जीत मान रहे हैं।

डोंबिवली स्थित पिंपलेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ा प्रकरण सिर्फ एक धार्मिक स्थल की कहानी नहीं, बल्कि धैर्य, संघर्ष और सामूहिक शक्ति का सशक्त उदाहरण है। हजारों श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने लगभग दो दशकों तक संघर्ष किया, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने मंदिर के लिए 4 एकड़ 25 गुंठा भूमि अंततः मंजूर कर दी।

संकल्प पूर्ति पूजन के साथ हुआ आभार व्यक्त

इस ऐतिहासिक फैसले के बाद महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक रविंद्र चव्हाण ने सोमवार तड़के अपनी पत्नी के साथ मंदिर में संकल्प पूर्ति पूजन किया। उन्होंने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह कदम हजारों शिवभक्तों की लंबे समय से चली आ रही मांग का परिणाम है।

दो दशक का संघर्ष, आखिरकार मिली जीत

राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंदिर की 4 एकड़ से अधिक भूमि को आधिकारिक रूप से मंदिर ट्रस्ट के नाम करने का निर्णय लिया गया, जिससे भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला है। रविंद्र चव्हाण ने बताया कि यह मुद्दा करीब 20 साल से लंबित था। ग्राम सभाओं, प्रशासनिक बैठकों और कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए लगातार प्रयास किए जाते रहे। 2012 में डोंबिवली बंद जैसे आंदोलन भी हुए, जिसके बाद अब जाकर यह मामला सुलझ पाया है।

8 जून को होगा भव्य शिवोत्सव

इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में 8 जून 2026 को मंदिर परिसर में भव्य शिवोत्सव और कृतज्ञता समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें भजन-कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान और सामूहिक प्रार्थना जैसे कार्यक्रम होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे और उद्योग मंत्री उदय सामंत सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है।

श्री पिंपलेश्वर महादेव मंदिर की क्या है खासियत?

डोंबिवली (पूर्व) के नांदिवली-सागाव क्षेत्र में स्थित श्री पिंपलेश्वर महादेव मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और गहरी धार्मिक आस्था के लिए जाना जाता है। लगभग 125 वर्ष पुराने इस जागृत देवस्थान की स्थापना स्वामी शिवानंद नामक एक तपस्वी ने एक पीपल के पेड़ के नीचे की थी, जिससे इसकी आध्यात्मिक परंपरा और भी विशेष मानी जाती है।

यह मंदिर कल्याण-शिळ रोड के पास लगभग सात एकड़ के शांत और हरियाली से भरे परिसर में स्थित है, जो इसे एक प्राकृतिक तीर्थ स्थल का स्वरूप देता है। इसकी महिमा को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इसे 'क' दर्जा तीर्थक्षेत्र का स्थान भी प्रदान किया है।

यहां हर वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य उत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और पूरा परिसर भक्ति और उत्सव के माहौल से भर जाता है।

शिवभक्तों की आस्था की जीत

चव्हाण ने कहा कि पिंपलेश्वर महादेव मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। भूमि विवाद खत्म होने से अब मंदिर में सुविधाओं के विकास का रास्ता भी साफ हो गया है। उन्होंने सभी शिवभक्तों और नागरिकों से 8 जून के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है।

आरसीबी का अनमोल हीरा, ट्रायल्स में हुआ रिजेक्ट, फिर फाइनल में मैच पलटकर कोहली की टीम को बनाया चैंपियन

(जीएनएस)।

आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस (GT) को हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने जब चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम की। इस जीत के बाद आरसीबी के अनुभवी गेंदबाज जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार के साथ एक और नाम पूरी दुनिया की जुबान पर है। यहां हम बात कर रहे हैं युवा तेज गेंदबाज रसिक सलाम डार की। मेगा ऑक्शन में आरसीबी द्वारा 6 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि में खरीदे गए रसिक ने इस सीजन में टीम के मुख्य ट्रम्प कार्ड की भूमिका निभाई।

रसिक सलाम डार के लिए शानदार रहा आईपीएल 2026

रसिक सलाम डार ने इस सीजन में 21.30 की शानदार औसत से कुल 19 विकेट चटकाए। इसके साथ ही वह टूनार्मेंट के आठवें सबसे सफल गेंदबाज भी रहे। इतना ही नहीं खिताबी यानी फाइनल मुकाबले में 3 अहम विकेट लेकर आरसीबी की जीत सुनिश्चित की। रसिक सलाम डार ने इस सीजन कई बार आरसीबी को मुश्किल परिस्थितियों से निकालने का काम कर चुके हैं।

इरफान ने पहचाना था रसिक का टैलेंट

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम के रहने वाले रसिक सलाम हर साल श्रीनगर में होने वाले क्रिकेट ट्रायल्स में हिस्सा लेते थे। लेकिन हर बार उन्हें शॉर्टलिस्ट न होने के कारण निराशा हाथ लगती थी। साल 2018 में भी जब वे ट्रायल देकर बिना किसी उम्मीद के अपना किटबैग उठाकर चचेरे भाई नदीम डार के साथ वापस लौट रहे थे, तब पूर्व भारतीय दिग्गज इरफान पठान की नजर उन पर पड़ी। इरफान ने रसिक के कलाई के अनूठे एक्शन और रफ्तार को तुरंत पहचान लिया। इरफान के विशेष प्रयासों के बाद रसिक को सीनियर अभ्यास मैचों में शामिल किया गया, जहां उन्होंने हैट्रिक लेकर अपनी काबिलियत साबित की।

करियर की शुरूआत में ही लगा था बैन

रसिक की प्रतिभा को देखकर मुंबई इंडियंस (MI) ने उन्हें साल 2019 में अपनी टीम में शामिल किया और उन्होंने डेब्यू भी किया। लेकिन इसके तुरंत बाद जन्म प्रमाण पत्र में विसंगति के कारण बीसीसीआई ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया। जब वे इस मानसिक आघात से उबरकर वापसी की तैयारी कर रहे थे, तब वे गंभीर रूप से चोटिल हो गए। रसिक को बेंगलुरु में करीब 6 महीने अकेले रहकर कड़े पुनर्वास से गुजरना पड़ा। इस कड़े दौर में उन्होंने अपनी गेंदबाजी तकनीक और एक्शन पर काम किया। बाद में घरेलू क्रिकेट में वे जम्मू-कश्मीर छोड़कर बड़ौदा की तरफ से खेलने लगे।

आरसीबी का दांव और कप्तान पाटीदार का भरोसा

आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के साथ एक साधारण सीजन के बाद आरसीबी ने मेगा ऑक्शन में उन पर 6 करोड़ की बड़ी बोली लगाई, जिसे कई विश्लेषकों ने उस समय एक जुआ माना था। लेकिन सीजन में यश दयाल की अनुपस्थिति में कप्तान रजत पाटीदार ने रसिक पर पूरा भरोसा जताया। कप्तान पाटीदार ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि रसिक अपनी स्किल्स, विशेषकर स्लोअर वन, बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी और यॉर्कर को लेकर बेहद स्पष्ट थे। जब भी वे मैदान पर उतरे, उनके पास अपनी भूमिका की पूरी क्लेरिटी थी।

27 छक्के और 400 से ज्यादा रनों से धमाल, आईपीएल के बाद भारत में एक और लीग शुरू, पहले मैच में तहलका

(जीएनएस)।

विदर्भ प्रीमियर लीग 2026 की शुरूआत 1 जून को बेहद रोमांचक अंदाज में हुई। ओपनिंग मुकाबला ठएउड मास्टर ब्लास्टर्स और पगारिया स्ट्राइकर्स के बीच खेला गया, जिसमें

कुल मिलाकर 442 रन और 27 छक्कों की बरसात देखने को मिली। इस हाई-स्कोरिंग मैच ने लीग के पहले ही दिन फैंस को पूरी तरह एंटरटेन कर दिया। इस मैच की सबसे खास बात रही रविकुमार समर्थ की शानदार शतकीय पारी, जिसने मुकाबले का पूरा रुख ही बदल दिया।

ठएउड मास्टर ब्लास्टर्स के विकेटकीपर बल्लेबाज तुषार कादू ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों में 87 रन जड़ दिए। उनकी पारी में 10 छक्के और 5 चौके शामिल रहे। सबसे खास पल छठे ओवर में आया, जब उन्होंने एक ही ओवर में 33 रन ठोक दिए। यह ओवर पगारिया स्ट्राइकर्स के गेंदबाज स्वपनिल सिंह ने डाला, जिनके खिलाफ तुषार ने 4 छक्के और 2 चौके जड़कर मैदान में हड़कंप मचा दिया।

इस मैच में गेंदबाज स्वपनिल सिंह भी चर्चा में रहे, जो इससे पहले आईपीएल में फ्ळड के लिए 7 मैच खेल चुके हैं और 6 विकेट भी हासिल कर चुके हैं। लेकिन इस मुकाबले में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। बल्लेबाजों ने उन्हें जमकर निशाना बनाया और उनकी गेंदबाजी पूरी तरह महंगी साबित हुई। एक ही ओवर में उन्होंने इतने रन लुटा दिए कि वह ओवर लीग के इतिहास में अब तक का सबसे महंगा ओवर माना जा रहा है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन के घर पर चोरी, लाखों के गहने-घड़ियां लेकर फरार हुई थी महिला, पुलिस ने की गिरफ्तारी

(जीएनएस)।

बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन के परिवार से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक्ट्रेस की बुजुर्ग मां के घर से लाखों रुपये के गहने और महंगी घड़ियां गायब होने के बाद पुलिस जांच में ऐसा खुलासा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया है। आरोप है कि जिस महिला पर परिवार ने वर्षों तक भरोसा किया, उसी ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

एक्ट्रेस रवीना टंडन के मां के घर पर हुई चोरी

पुलिस जांच के अनुसार गिरफ्तार की गई 47 वर्षीय महिला पिछले कई वर्षों से टंडन परिवार के संपर्क में थी। वह घर के कामकाज में मदद करने के साथ-साथ रवीना टंडन की 86 वर्षीय मां की देखभाल भी करती थी। नियमित रूप से घर आने-जाने के कारण उसने परिवार का विश्वास हासिल कर लिया था और घर के माहौल से पूरी तरह परिचित हो चुकी थी।

भरोसे का फायदा उठाकर महिला ने घर में बनाई जगह

पुलिस के अनुसार इसी भरोसे का फायदा उठाकर उस महिला ने एक्ट्रेस की मां के घर में रखी कीमती संपत्ति पर नजर बनाई और मौका मिलते ही बड़ी चोरी को अंजाम दे दिया। इस घटना ने एक्ट्रेस के परिवार वालों के साथ साथ उनके करीबियों को भी हैरान कर दिया है।

तिजोरी से गायब हुए लाखों के गहने

-मामला तब सामने आया जब टंडन परिवार ने घर में रखी ज्वैलरी और कुछ महंगी घड़ियों को तलाशना चाहा लेकिन वो अपनी जगह पर नहीं मिलीं। शुरूआती जांच में पता चला कि कीमती सामान जिस लॉकर में रखा गया था, उससे छेड़छाड़ की गई थी।

-पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला पर आरोप है कि उसने तिजोरी से करीब 25 लाख रुपये के गहने और दो बेशकीमती लग्जरी घड़ियां निकाल ली हैं। परिवार को जब इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत मामले की जांच शुरू की।

पूछताछ में सामने आए कई खुलासे

-शुरूआती पूछताछ के दौरान महिला ने चोरी में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया था। हालांकि बाद में पूछताछ का दायरा बढ़ने पर उसने कथित तौर पर कुछ घड़ियां वापस कर दीं। इसके साथ ही उसने दावा किया कि बाकी गहने किसी अन्य व्यक्ति के पास हैं और उन्हें जल्द लौटा दिया जाएगा।

-वहीं समय बीतने के बावजूद जब कीमती सामान वापस नहीं मिला, तब परिवार को संदेह और गहरा हो गया। इसके बाद मामले को पुलिस तक पहुंचाया गया।

परिवार को कथित धमकी देने का भी आरोप

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी महिला पर परिवार के एक सदस्य को धमकाने का भी आरोप है। कहा जा रहा है कि जब उससे गहनों को लेकर दबाव बनाया गया तो उसने कथित तौर पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी थी। इसी बीच परिवार ने अपने स्तर पर भी सामान की तलाश जारी रखी लेकिन सफलता नहीं मिलने के बाद औपचारिक शिकायत दर्ज कराने का फैसला लिया गया।

शिकायत के बाद तेज हुई पुलिस जांच

-मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद मुंबई के जुहू पुलिस ने जांच शुरू की और उपलब्ध सबूतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और चोरी हुए सामान की बरामदगी के लिए अलग-अलग पहलुओं पर जांच शुरू की।

-फिलहाल पुलिस बाकी ज्वैलरी और अन्य कीमती सामान की तलाश में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही चोरी की पूरी कड़ी का खुलासा हो सकता है।

रवीना टंडन के परिवार की सुरक्षा पर उठे सवाल

ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि लंबे समय तक बने भरोसे का गलत इस्तेमाल कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। रवीना टंडन के परिवार से जुड़ी इस घटना ने न सिर्फ सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं बल्कि ये भी याद दिलाया है कि घर में आने-जाने वाले लोगों पर भरोसा करते समय सतर्कता बरतना कितना जरूरी है। अब सभी की नजरें पुलिस जांच और चोरी हुए बाकी कीमती सामान की बरामदगी पर टिकी हुई हैं।

गाय विश्व माता है, सीएम योगी ने बिल्कुल ठीक कहा जगद्गुरु रामभद्राचार्य

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गाय को लेकर दिए गए बयान पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि गाय विश्व माता है।

(जीएनएस)।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गाय को लेकर दिए गए बयान पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि गाय विश्व माता है।

मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा है। गाय स्वयं मां हैं, गोवध बंद होने का एक ही उपाय है, अगले निर्वाचन में हिंदुत्ववादियों को 370 सीटें मिल जाएं तो तुरंत गोवध बंद हो जाएगा। हम लोग गोवध बंद करवाकर रहेंगे, लेकिन हमको हिंदुत्ववादियों की 370 सीटें लोकसभा में चाहिए। यह 2029 तक हो जाएगा।

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि यूपी में फिर कमल खिलेगा। 'चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों' यह मेरा संदेश है।

बंगाल को लेकर उन्होंने कहा कि बंगाल में बहुत उत्पीड़न किया गया है। पहले जब हम बंगाल में जाते थे तो लगता था कि हम पाकिस्तान में आए हैं। उन्होंने कहा कि रामजी के आदर्श पर जब देश चलेगा तो कदाचार, व्यभिचार, अत्याचार और अनाचार सब मिट जाएंगे। युवक, किशोरियां चरित्रवान होंगी।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि अपनी छवि के लिए कभी राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम कहते हैं कि जब गंगा स्नान के समय पुलिस ने कह दिया था कि भगवान यहीं तक सभी लोग जाते हैं, तब पालकी से गंगा तट पर उनको जाने की क्या आवश्यकता थी? क्या यही साधुता है? एक साधुत्व वह था कि हम लोग पैदल जाते थे। आदि शंकराचार्य पैदल आए और ये गंगा के प्रवाह तक पालकी से जाना चाहते हैं।

गाजियाबाद एनकाउंटर पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य बोले कि अपराध देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। बकरीद के मौके पर एक निर्दोष लड़के की हत्या कर देना, ये क्या था? क्या वो धर्म था? ऐसे का एनकाउंटर हुआ तो कौन सी बड़ी बात हो गई? उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता ही भारत की बदनामी करते हैं। हमारे विपक्षी नेता पानी पी-पीकर देश की बदनामी करते हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने सीतापुर के मेधावियों को किया सम्मानित, एक लाख रुपये, टैबलेट और मेडल मिला

(जीएनएस)।

सीतापुर। यूपी बोर्ड की दसवीं व बारहवीं की परीक्षा में प्रदेश की मेरिट में आने वाले जिले 17 बच्चों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सम्मानित किया। इनमें दसवीं के 13 व बारहवीं के चार परीक्षार्थी हैं।

इनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक-एक लाख रुपये की चेक, टैबलेट, मेडल प्रदान किया। 12वीं की अंशिका वर्मा, अनुष्का वर्मा, ज्ञानेंद्र वर्मा, अंशी मौर्या समेत आठ छात्र-छात्राओं को राजकीय इंटर कालेज में सम्मानित किया गया।

मुख्य अतिथि कारागार राज्यमंत्री राकेश राठौर गुरू ने कहा कि यह हमारे जनपद के लिए गौरव की बात है कि मेधावियों ने जिले का नाम प्रदेश स्तर तक पहुंचाया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है।

प्रत्येक वर्ष प्रदेश के टापर जिले के मेधावियों बनते हैं या फिर टाप टेन में स्थान बनाते हैं। यह विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन और अभिभावकों की उनके करियर को लेकर संजीदगी व प्रयासों से संभव हो पाता है।

मिश्रिख विधायक रामकृष्ण भार्गव ने कहा कि जिले मेधावियों में हम सबकों गर्व हे। यह बच्चे एक दिन पूरे देश में जिले का नाम रोशन करेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ल ने कहा कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। सभी मेधावियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।

मुख्य विकास अधिकारी डा. दीक्षा जोशी ने कहा कि सकारात्मक रहते हुए विद्यार्थी पढ़ाई करने पर सफलता अवश्य मिलती है। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि प्रत्येक मेधावी को 21-21 हजार रुपये, अंगवस्त्र व ओडीओपी दरी भेंट की गई है।

आईएनएस सुदर्शनी ने एंटीगुआ में अपना बंदरगाह भ्रमण संपन्न किया

(जीएनएस)।

आईएनएस सुदर्शनी ने 31 मई, 2026 को चार दिवसीय सफल बंदरगाह यात्रा पूर्ण करने के उपरांत एंटीगुआ से प्रस्थान किया। लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत संपन्न यह यात्रा कैरेबियाई देशों के साथ भारत की समुद्री पहुंच, सहभागिता और रणनीतिक जुड़ाव को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस यात्रा से भारत और एंटीगुआ के बीच समुद्री सहयोग को नई मजबूती मिली है।

इस यात्रा के दौरान आईएनएस सुदर्शनी ने अनेक गणमान्य अतिथियों की मेजबानी की, जिनमें एंटीगुआ और बारबुडा के माननीय प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन भी शामिल थे। बंदरगाह प्रवास के दौरान आईएनएस सुदर्शनी के कमांडिंग ऑफिसर ने ब्रिगेडियर टेल्बर्ट बेंजामिन से शिष्टाचार भेंट की।

पेशेवर आदान-प्रदान कार्यक्रमों ने समुद्री संबंधों को और सुदृढ़ किया। जहाज को स्थानीय नागरिकों व आगंतुकों के लिए भी खुला रखा गया,

भारतीय नौसेना व एंटीगुआ तथा बारबुडा रक्षा बल के बीच सहयोग एवं जिससे उन्हें भारतीय नौसेना की समृद्ध समुद्री विरासत, नौकायन कौशल एवं पारंपरिक प्रशिक्षण पद्धतियों को निकट से देखने और समझने का अवसर प्राप्त हुआ।

यह बंदरगाह यात्रा महासागर तथा वसुधैव कुटुंबकम—विश्व एक परिवार है, की भावना के अनुरूप स्थायी समुद्री साझेदारियों को सुदृढ़ करने और अंतरराष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देने के प्रति भारत की अटूट वचनबद्धता को रेखांकित करती है। एंटीगुआ में अपनी सफल यात्रा पूर्ण करने के बाद आईएनएस सुदर्शनी अब अमेरिका की ओर अग्रसर है, जहां वह अंतर्राष्ट्रीय नौसेना समीक्षा और अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतिष्ठित 'सेल 250' समारोह में भाग लेगा।

ट्विशा की तरह ससुराल में मानसी की रहस्यमय मौत! 3 दिन बाद अरेस्ट इंफ्लुएंसर पति के कबूलनामे में क्या-क्या?

(जीएनएस)।

भोपाल के ट्विशा शर्मा डेथ मिस्ट्री की तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मानसी की मौत की गुत्थी भी उलझती जा रही है। मात्र 23 साल की इंफ्लुएंसर मानसी की ससुराल में हुई संदिग्ध मौत पर परिजनों ने हत्या का आरोप उसके पति पर लगाया है। मामले में फरार मुख्य आरोपी और उसके पति सागर लोधी (29) को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में तीन दिन से दुबका हुआ था और डिस्चार्ज होते ही शहर छोड़कर फरार होने की तैयारी में था। सआदतगंज पुलिस की टीम ने ट्रॉमा सेंटर यूनिट-1 के बाहर उसे दबोच लिया।

यह मामला सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि सोशल मीडिया की चमकदार दुनिया के पीछे छिपे क्रूर यथार्थ की तस्वीर है। जहां 7.93 लाख फॉलोअर्स वाला इंफ्लुएंसर पति अपनी पत्नी से स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग पूरी न होने पर मारपीट और प्रताड़ना करता था। आइए विस्तार से जानते हैं...

अस्पताल से निकलते ही पकड़ा गया, क्या कबूला?

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के अभियान के तहत सहायक पुलिस आयुक्त बाजारखाला और प्रभारी निरीक्षक सआदतगंज के निर्देशन में कार्रवाई हुई। 2 जून सुबह करीब 11:30 बजे मुखबिर की सूचना पर टीम ट्रॉमा सेंटर पहुंची। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर बाहर निकलते सागर को रोककर पूछताछ की गई। रिकॉर्ड चेक करने पर उसकी पहचान मुकदमा नंबर 111/2026 का मुख्य आरोपी के रूप में हुई।

प्रारंभिक पूछताछ में सागर ने स्वीकार किया कि वह गिरफ्तारी से बचने के लिए अस्पताल में छिपा था। पुलिस अब उसे हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। अन्य नामजद आरोपियों (ससुर राजेश, ननद बरखा-चांदनी, ननदोई अनु और बुआ सास आशा) की तलाश में छापेमारी जारी है।

31 मई 2026 को कानपुर के टीपी नगर बगाही निवासी सुनील कुमार वर्मा (मानसी के चाचा) ने सआदतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि शादी के बाद ससुराल पक्ष लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहा था। शादी में 7 लाख रुपये नगद, तिलक और घर का सामान देने के बावजूद वे स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर मानसी को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जाती थी। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2), 85 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

मानसी कानपुर की रहने वाली 23 वर्षीय युवती थीं। वे सोशल मीडिया पर सक्रिय इंफ्लुएंसर थीं और अपनी खुशहाल जिंदगी की रील्स पोस्ट करती थीं। उनकी शादी 9 दिसंबर 2024 को लखनऊ के सआदतगंज निवासी सागर राजपूत (लोधी) से हुई थी। दोनों का 6 महीने का बेटा भी है।

सागर का इंस्टाग्राम अकाउंट @sagarkds पर 7.93 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। बाहर से देखने पर दंपति की जिंदगी परफेक्ट लगती थी - रोमांटिक रील्स, मुस्कुराते चेहरे। लेकिन अंदर क्या चल रहा था, यह मौत के बाद सामने आया।

मौत से महज दो दिन पहले, 29 मई को मानसी ने सागर के साथ रोमांटिक रील पोस्ट की थी, जिसमें उन्हें 'माई लव' कहा था। 30 मई शाम को उनका शव घर में फंदे से लटका मिला।

मानसी के परिजनों का आरोप है कि यह सुसाइड नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर है। चाचा अविनाश राजपूत ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खुलासा किया कि शादी के शुरूआती महीनों के बाद रोज मारपीट शुरू हो गई। पति अक्सर घर छोड़कर भाग जाता था। एक बार रात 2 बजे मानसी ने वीडियो कॉल पर रोते हुए बताया कि सागर ने पूरे कमरे का सामान तोड़ दिया है।

परिवार कई बार लखनऊ आया और समझौता कराया, लेकिन ससुराल वालों की मांगें बढ़ती गईं। नया मकान ससुर के नाम और स्कॉर्पियो गाड़ी। मौत वाले दिन मानसी कई दिनों से डरी हुई आवाज में बात कर रही थी। परिवार का कहना है कि शव की स्थिति (पैर जमीन को छू रहे थे) साफ संकेत दे रही है कि उसे मारकर फंदे पर लटकाया गया। वारदात के बाद पूरा परिवार ताला लगाकर फरार हो गया, जिसने शक और गहरा कर दिया।

सोशल मीडिया वर्सेज हकीकत: एक विडंबना

यह मामला सोशल मीडिया युग की बड़ी विडंबना उजागर करता है। एक तरफ चमकदार रील्स, दूसरी तरफ घरेलू हिंसा। मानसी जैसी युवतियां बाहर खुश दिखाती हैं, लेकिन अंदरूनी तनाव किसी को पता नहीं चलता। इस घटना ने दहेज प्रथा की जड़ों पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर शिक्षित और सोशल मीडिया वाले परिवारों में।

पुलिस की भूमिका और आगे की जांच

सआदतगंज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक विशाल कुमार यादव, जितेंद्र कुमार वर्मा, विशाल पटेल और अन्य जवान शामिल हैं।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य, कॉल डिटेल्स और डिजिटल सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की गहन छानबीन की जाएगी और बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सागर लोधी की गिरफ्तारी से गुत्थी सुलझने की दिशा में पहला कदम बढ़ा है, लेकिन सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है। क्या यह खुदकुशी थी या क्रूर हत्या? पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक और पूछताछ के जवाब तय करेंगे। पुलिस पर दबाव है कि पूरे साजिशकताओं को पकड़कर सख्त सजा दिलाई जाए। लखनऊ की इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है।

'पैसे को सिर पर मत चढ़ने देना', वैभव सूर्यवंशी को आखिर दिग्गज ने क्यों दी ऐसी सलाह?

(जीएनएस)।

आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने का काम किया। जिस उम्र में ज्यादातर खिलाड़ी अपने करियर की शुरूआत करने का सपना देखते हैं, उस उम्र में वैभव ने दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों के खिलाफ रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी। वैभव ने आईपीएल 2026 में 16 मैचों में 776 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 237.3 का रहा और उन्होंने 72 छक्के जड़े।

ललित मोदी ने दिया बड़ा बयान

इसी बीच एक इंटरव्यू में आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसने सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान खींच लिया। बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर पूर्व कछछ चेयरमैन ललित मोदी ने बड़ी भविष्यवाणी की है। मोदी का मानना है कि वैभव आने वाले वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े खेल सितारों में शामिल हो सकते हैं और लोकप्रियता के मामले में हॉलीवुड व बॉलीवुड के कई बड़े सितारों को भी पीछे छोड़ सकते हैं।

मोदी ने की वैभव की जमकर तारीफ

एक इंटरव्यू के दौरान ललित मोदी ने वैभव की प्रतिभा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि युवा बल्लेबाज में भविष्य में टी-20 क्रिकेट का पहला दोहरा शतक लगाने की क्षमता है। इसके साथ ही मोदी ने उन्हें सलाह देते हुए कहा कि सफलता और पैसा कभी उनके सिर पर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि सही सोच और मेहनत के साथ वह क्रिकेट जगत के सबसे बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं।

फ्रेंचाइजी क्रिकेट को बताया भविष्य

ललित मोदी ने युवा खिलाड़ियों के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बजाय फ्रेंचाइजी लीगों को प्राथमिकता देने के बढ़ते चलन का भी समर्थन किया। उनका मानना है कि आने वाले समय में क्रिकेट की दुनिया इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जैसे बास्केटबॉल खिलाड़ी ठइअ में खेलने का सपना देखते हैं और फुटबॉल खिलाड़ी प्रीमियर लीग क्लबों के लिए खेलना चाहते हैं, उसी तरह क्रिकेट में भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट का महत्व लगातार बढ़ेगा।

संजय मांजरेकर ने दी सावधानी बरतने की सलाह

पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने वैभव सूर्यवंशी के करियर लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। मांजरेकर का मानना है कि युवा बल्लेबाज को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जल्दबाजी में चुनौतीपूर्ण विदेशी परिस्थितियों में नहीं उतारना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय टीम वैभव को मौका देती है, तो शुरूआत में उन्हें उन परिस्थितियों में खिलाया जाना चाहिए जो कछछ जैसी बल्लेबाजी के लिए अनुकूल हों।

मांजरेकर के मुताबिक न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी तेज और उछालभरी पिचों पर तुरंत मौका देना सही रणनीति नहीं होगी। उनका मानना है कि युवा खिलाड़ी को धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय स्तर की चुनौतियों के लिए तैयार किया जाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने असम के मूगा रेशम के लिए 'सेनेहजोरी' मिशन का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर पूर्वोत्तर विजन को मिशन सेनेहजोरी में साकार होते देखा जा सकता है - इसका उद्देश्य असम के सुनहरे रेशम को वैश्विक लक्जरी ब्रांड में बदलना है

केंद्रीय मंत्री ने प्रीमियम मूगा रेशम और लक्जरी वस्त्र मूल्य श्रृंखलाओं के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की असम की क्षमता के बारे में बताया

(जीएनएस)।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री (एमडीओएनईआर) श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज असम के माननीय मुख्यमंत्री के साथ मिलकर मिशन "सेनेहजोरी" - असम मूगा सिल्क यूएसपी का शुभारंभ किया। यह एक व्यापक क्लस्टर-आधारित पहल है। इसका उद्देश्य असम के अद्वितीय मूगा रेशम क्षेत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी, उच्च मूल्य वाले लक्जरी वस्त्र इकोसिस्टम में परिवर्तित करना है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा असम सरकार, केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/संगठनों के समन्वय से संचालित यह मिशन, मेजबान पौधे की खेती और रेशमकीट के बीज उत्पादन से लेकर रीलिंग, बुनाई, ब्रांडिंग, निर्यात संवर्धन, डिजिटल ट्रेसबिलिटी और पर्यटन तक संपूर्ण मूगा रेशम मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने का प्रयास करता है।

मुगा रेशम को दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक रूप से सुनहरा रेशम और भारत का पहला जीआई-टैग प्राप्त रेशम माना जाता है। यह असम में लगभग 2.6 लाख रेशम पालकों और बुनकरों के परिवारों को आजीविका प्रदान करता है। अपनी दुर्लभता और वैश्विक मान्यता के बावजूद, यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। मिशन सेनेहजोरी एक प्रीमियम, पता लगाने योग्य और निर्यात-उन्मुख मुगा रेशम अर्थव्यवस्था का निर्माण करके इस मूल्य अंतर को पाटने का प्रयास करता है।

इस मिशन में जोरहाट, शिवसागर, लखीमपुर, धेमाजी, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, माजुली और सुआलकुची सहित प्रमुख मूगा रेशम उत्पादक जिलों को शामिल है और ये क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है। इस पहल का उद्देश्य मेजबान पौधे की पारिस्थितिकी को मजबूत करना, आधुनिक रीलिंग अवसंरचना स्थापित करना, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना, साझा सुविधा केंद्र (सीएफसी) बनाना, जीआई प्रमाणीकरण को लागू करना और "सेनेहजोरी" की एकीकृत ब्रांड पहचान के तहत वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाना है ।

केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र की अनूठी खूबियों और उत्पादों को वैश्विक मान्यता दिलाने और स्थानीय समुदायों के लिए स्थायी आजीविका उत्पन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि असम का मूगा रेशम केवल एक वस्त्र उत्पाद नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मिशन सेनेहजोरी की परिकल्पना न केवल "संपूर्ण सरकारी" सिद्धांत पर आधारित है, बल्कि इसमें केंद्रीय मंत्रालयों, असम सरकार, तकनीकी संस्थानों और निजी क्षेत्र के भागीदारों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए "संपूर्ण सरकारी" दृष्टिकोण को अपनाया गया है। तीन वर्षों की अवधि में (एमडीओएनईआर के 136झ151 करोड़ रुपये सहित) लगभग 396झ411 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ मिशन का उद्देश्य विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त लक्जरी मूगा रेशम इकोसिस्टम का निर्माण करना, उत्पादकों के लिए मूल्य प्राप्ति को बढ़ाना और असम को रेशम आधारित सांस्कृतिक और अनुभवात्मक पर्यटन के लिए एक अग्रणी गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

गुजरात के छात्र प्रतिनिधिमंडल ने ओडिशा के सांस्कृतिक, शैक्षिक और विकासात्मक परिदृश्य का अवलोकन किया

ओडिशा के राज्यपाल ने युवा संगम के छठे चरण के तहत गुजरात के छात्र प्रतिनिधिमंडल से परस्पर बातचीत की

(जीएनएस)।

ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कम्भमपति ने 27 मई 2026 को युवा संगम के छठे चरण में भाग लेने वाले गुजरात के छात्र प्रतिनिधिमंडल के साथ परस्पर बातचीत की।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) अहमदाबाद के नेतृत्व में छात्र प्रतिनिधिमंडल ने 22 मई 2026 को ओडिशा में अपने शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान दौरे का आरंभ किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी) राउरकेला द्वारा आयोजित इस प्रतिनिधिमंडल का

25 मई 2026 को गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यह राज्य भर में गहन शिक्षण और सांस्कृतिक आदान-प्रदान यात्रा की शुरूआत का प्रतीक है।

इस संवाद के दौरान राज्यपाल ने राष्ट्र निर्माण, निर्माण, सांस्कृतिक समझ और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करने में युवाओं की भूमिका रेखांकित की। इस सत्र ने प्रतिभागियों को नेतृत्व, नागरिक उत्तरदायित्व और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से एकता को बढ़ावा देने के महत्व के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की।

अपनी यात्रा के दौरान, छात्र प्रतिनिधिमंडल ने ओडिशा के समृद्ध सांस्कृतिक, शैक्षिक और विकासात्मक परिदृश्य का अवलोकन किया। प्रतिभागियों ने कोणार्क सूर्य मंदिर और माँ समलेश्वरी मंदिर जैसे प्रतिष्ठित स्थलों का दौरा किया और राज्य की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्थानीय कारीगरों के साथ परस्पर बातचीत के माध्यम से ओडिशा की जीवंत वस्त्र परंपराओं का भी अनुभव किया और सांस्कृतिक आदान-प्रदान एवं पारंपरिक प्रदर्शनों के माध्यम से मुंडा जनजातीय समुदाय के साथ जुड़ाव स्थापित किया।

छात्र प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा आयोजित एक सत्र में भाग लिया, जिसमें भारत की भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला की एफबीटीबीआई प्रयोगशाला, राउरकेला इस्पात संयंत्र, हीराकुड बांध और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का भी दौरा किया। इससे उन्हें ओडिशा के नवाचार इकोसिस्टम, औद्योगिक विकास, इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और खेल अवसंरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई।

सतत विकास पर केंद्रित गतिविधियों के अंतर्गत, छात्र प्रतिनिधिमंडल ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में भाग लिया, जिसमें उन्होंने पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण तथा जैविक खेती के तरीकों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। यह यात्रा 30 मई 2026 को एक समापन कार्यक्रम के साथ सम्पन्न हुई, जो युवा संगम के अंतर्गत सीखने, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और राष्ट्रीय एकता की एक सार्थक यात्रा की परिणति का प्रतीक है।